EMPOWER IAS
The Power To Pursue Your Dreams

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Saturday, 27 July , 2024

Edition: International Table of Contents

Page 03 **Syllabus : GS 2 : भारतीय राजनीति**	उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 219 प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है केंद्र
Page 04 **Syllabus : GS 2 : अंतर्राष्ट्रीय संबंध**	आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति की आधारशिला है: जयशंकर
Page 05 **Syllabus : प्रारंभिक तथ्य**	असम के शाही दफन टीले अब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल
Page 14 **Syllabus : प्रारंभिक तथ्य**	पेरिस ने धूमधाम, उत्साह और भव्यता के साथ अंतिम तमाशा का अनावरण किया
समाचार में शब्द	डार्क ऑक्सीजन
Page 06 : संपादकीय विश्लेषण: **पाठ्यक्रम** **GS: 02 : अंतर्राष्ट्रीय संबंध : भारत और उसके पड़ोस**	बंगाल की खाड़ी में एक नया प्रयास
मानचित्र	विषय: भारत के टाइगर रिजर्व

Page 3 : GS 2: Indian Polity : Executive & Judiciary

केंद्र सरकार ने कहा है कि कॉलेजियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 219 प्रस्ताव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं।

219 proposals for High Court judges' appointment are being processed: Centre

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The Union government said 219 proposals for the appointment of High Court judges across the country are in various stages of processing.

Union Law Minister Arjun Meghwal, responding to questions raised by Rajya Sabha Member Haris Beeran, said the Supreme Court Collegium (SCC), as of July 19, has processed 82 of the 90 proposals sent to it by the government for advice.

"One hundred and twenty-nine fresh proposals received recently are being processed for seeking the advice of the SCC," the reply said.

High Courts have still not sent recommendations on the remaining 138 vacancies.

Against the total sanctioned strength of 1,114 judges in various High Courts, 357 posts are lying vacant.

Against the total sanctioned strength of 1,114 judges, 357 posts are vacant

Chief Justices of the High Courts are required to initiate the proposal to fill up a vacancy of a High Court judge six months prior to the occurrence of the vacancy. "However, this timeline is often not adhered to by the High Courts," the government complained. Names recommended by the High Court Collegium are sent with the views of the government to the SCC for advice. Recommendation of the SCC is mandatory for appointment.

"Appointment of Judges in the High Courts is a continuous, integrated and collaborative process, involving approval from various constitutional authorities," the government assured.

Collegium inputs

The process of finalising a revised Memorandum of Procedure for Appointment of Judges to the Supreme Court and High Courts to bring in more transparency and accountability in the appointment process has not seen the light of the day. The government claims it is waiting for the Collegium's inputs on a draft while the latter maintained that it has already given its final views about the draft in March 2017, and has nothing more to add.

Meanwhile, the government said it is considering a proposal for the transfer of five High Court judges.

"No timeline has been prescribed in the MoP for transfer of judges from one High Court to another," it explained.

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएँ:

- संविधान के अनुच्छेद 124(3) के अनुसार, किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है, यदि वह:
  - भारत का नागरिक हो।
  - कम से कम पाँच वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो या लगातार दो ऐसे न्यायालयों में कार्य कर चुका हो।
  - वैकल्पिक रूप से, कम से कम दस वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो या लगातार दो या अधिक ऐसे न्यायालयों में कार्य कर चुका हो।

- राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएँ:

- व्यक्ति ने भारत में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद संभाला हो, या
- कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो।
- व्यक्ति को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत नामांकित होना चाहिए।

कॉलेजियम द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:

CJI की नियुक्ति

- भारत के राष्ट्रपति CJI और अन्य SC न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।
- जहां तक सीजेआई का सवाल है, निवर्तमान सीजेआई अपने उत्तराधिकारी की सिफारिश करता है।
- व्यवहार में, 1970 के दशक के सुपरसेशन विवाद के बाद से यह सख्ती से वरिष्ठता के आधार पर होता रहा है।
- केंद्रीय कानून मंत्री सिफारिश को प्रधानमंत्री के पास भेजते हैं, जो बदले में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं।

अन्य सुप्रीम कोर्ट जज:

- शीर्ष अदालत के अन्य जजों के लिए, प्रस्ताव सीजेआई द्वारा शुरू किया जाता है।
- सीजेआई कॉलेजियम के बाकी सदस्यों के साथ-साथ उस उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश से भी परामर्श करता है, जिससे अनुशंसित व्यक्ति संबंधित है।
- परामर्शदाताओं को अपनी राय लिखित रूप में दर्ज करनी चाहिए और इसे फ़ाइल का हिस्सा बनाना चाहिए।
- कॉलेजियम सिफारिश को कानून मंत्री को भेजता है, जो इसे राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री को भेजता है।

उच्च न्यायालयों के लिए:

- उच्च न्यायालयों के सीजे की नियुक्ति संबंधित राज्यों के बाहर से मुख्य न्यायाधीश रखने की नीति के अनुसार की जाती है। पदोन्नति पर कॉलिजियम निर्णय लेता है।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संस्तुति मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाले कॉलेजियम द्वारा की जाती है।
- हालांकि, प्रस्ताव संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से शुरू किया जाता है।
- संस्तुति मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो राज्यपाल को प्रस्ताव केंद्रीय कानून मंत्री को भेजने की सलाह देते हैं।

कॉलेजियम प्रणाली क्या है?

- कॉलेजियम प्रणाली भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है।
- यह भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का आविष्कार है।
- संविधान में 'कॉलेजियम' शब्द का उल्लेख नहीं है।

संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 124: राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।

- अनुच्छेद 217: राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।

संरचना:

- सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम:
- पांच सदस्यीय निकाय।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की अध्यक्षता में।
- इसमें उस समय के सर्वोच्च न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।

उच्च न्यायालय कॉलेजियम:

- संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में।
- इसमें उस उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
- उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा नियुक्तियों के लिए सिफारिशें सीजेआई और सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुमोदन के बाद ही सरकार को भेजी जाती हैं।

UPSC Prelims PYQ : 2012

प्रश्न: भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा के लिए क्या प्रावधान है?

1. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय, भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना होता है।
2. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही हटाया जा सकता है।
3. न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि से लिया जाता है, जिस पर विधायिका को मतदान नहीं करना पड़ता है।
4. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियाँ भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद ही सरकार द्वारा की जाती हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 3 और 4
(c) केवल 4
(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: a)

Page 04 : International Relations

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए 'मॉडल कौशल ऋण योजना' को नया रूप दिया है, जिसमें ऋण की अधिकतम सीमा 7.5 लाख रुपये कर दी गई है।

INBRIEF

ASEAN cornerstone of India's Act East Policy: Jaishankar

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) was the cornerstone of India's Act East Policy and its Indo-Pacific vision, External Affairs Minister S. Jaishankar said on Friday, as he sought to expand cooperation with the bloc. Mr. Jaishankar was in the Laotian capital of Vientiane to participate in the meetings of ASEAN members. In his remarks at the opening session of the ASEAN-India Foreign Ministers Meeting, he said, "The current political, economic and security cooperation with ASEAN is of the utmost priority so is the people-to-people linkages, that we are constantly seeking to expand." Mr. Jaishankar's visit to Laos was of particular significance as this year marked a decade of India's Act East Policy, which was announced by Prime Minister Narendra Modi in 2014, the Ministry of External Affairs said. PTI

आसियान के बारे में:

- दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन (आसियान) दस दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से मिलकर बना एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है।
- 8 अगस्त, 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में स्थापित, इसके सदस्यों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार (बर्मा) और कंबोडिया शामिल हैं।

- आसियान का उद्देश्य सहयोग और संवाद के माध्यम से क्षेत्रीय शांति, स्थिरता, आर्थिक विकास और सामाजिक-सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना है।
- इसके प्रमुख सिद्धांतों में आपसी सम्मान, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, शांतिपूर्ण विवाद समाधान और आपसी लाभ के लिए सहयोग शामिल हैं।
- आसियान ने क्षेत्रीय एकीकरण और सहयोग को बढ़ाने के लिए आसियान आर्थिक समुदाय (एईसी), आसियान राजनीतिक-सुरक्षा समुदाय (एपीएससी) और आसियान सामाजिक-सांस्कृतिक समुदाय (एएससीसी) जैसे विभिन्न ढांचे और तंत्र स्थापित किए हैं।
- आसियान शिखर सम्मेलन संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जहाँ सदस्य देश क्षेत्रीय नीतियों और पहलों पर चर्चा और समन्वय करते हैं।
- आसियान ने प्रमुख शक्तियों और क्षेत्रीय संगठनों के साथ साझेदारी और संवाद तंत्र विकसित किए हैं, जो क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि में योगदान करते हैं।
- संगठन क्षेत्रीय विवादों, अंतरराष्ट्रीय अपराध, आतंकवाद, प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरणीय मुद्दों सहित विभिन्न क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करता है।
- आसियान आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र (AFTA) और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण प्रयासों जैसी पहलों के माध्यम से अंतर-क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है।
- यह दक्षिण पूर्व एशिया के भू-राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने और विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत-आसियान संबंध:

भारत के लिए महत्व:

- भारत की एक्ट ईस्ट नीति आसियान के साथ अपने रणनीतिक स्थान और आर्थिक क्षमता को देखते हुए उसके साथ जुड़ाव को गहरा करने पर जोर देती है।
- आसियान भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार सालाना अरबों डॉलर तक पहुँचता है।
- आसियान के साथ संबंधों को मजबूत करने से भारत का क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ता है और दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों तक पहुँच मिलती है।
- आसियान देशों के साथ सहयोग कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है और लोगों के बीच आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाता है।
- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच जैसे आसियान के नेतृत्व वाले मंचों में भारत की सदस्यता इसकी क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना को मजबूत करती है।

चुनौतियाँ:

- सीमित भौतिक संपर्क और बुनियादी ढाँचा भारत और आसियान के बीच व्यापार और निवेश प्रवाह में बाधाएँ पैदा करता है।
- गैर-टैरिफ बाधाएँ और नौकरशाही बाधाएँ निर्बाध आर्थिक एकीकरण में बाधा डालती हैं।
- चीन और जापान जैसी अन्य क्षेत्रीय शक्तियों से प्रतिस्पर्धा आसियान में भारत के प्रभाव को चुनौती देती है।
- आसियान सदस्यों के बीच ऐतिहासिक और क्षेत्रीय विवाद क्षेत्रीय सहयोग और एकता को जटिल बनाते हैं।
- सामाजिक-सांस्कृतिक मतभेद और भाषाई बाधाएँ लोगों के बीच घनिष्ठ संबंधों में बाधा डालती हैं।

आगे की राह:

- बुनियादी ढाँचे के विकास और डिजिटल पहलों को बढ़ावा देने के माध्यम से भौतिक और डिजिटल संपर्क को बढ़ाएँ।
- व्यापार बाधाओं को कम करने और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए व्यापक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत करें।
- भारत-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए समुद्री सहयोग को मजबूत करें।
- आपसी समझ और विश्वास को गहरा करने के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान और शैक्षिक कार्यक्रमों को बढ़ाएँ।
- क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करने और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आसियान के नेतृत्व वाले मंचों का लाभ उठाएँ।
- आसियान देशों के साथ आर्थिक संबंधों से परे रणनीतिक, सुरक्षा और सामाजिक-सांस्कृतिक आयामों को शामिल करते हुए उनके साथ जुड़ाव को विविधतापूर्ण और गहरा बनाना।

UPSC Prelims PYQ : 2018

प्रश्न: निम्नलिखित देशों पर विचार करें:

1. ऑस्ट्रेलिया
2. कनाडा
3. चीन
4. भारत
5. जापान
6. यूएसए

उपर्युक्त में से कौन-से देश आसियान के 'मुक्त-व्यापार साझेदार' हैं?

(a) 1, 2, 4 और 5
(b) 3, 4, 5 और 6
(c) 1, 3, 4 और 5
(d) 2, 3, 4 और 6

उत्तर: (c)

असम के अहोम राजवंश की 700 साल पुरानी अनूठी टीला-दफ़नाने की व्यवस्था चराईदेव मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है।

स्थान

- जबकि चराईदेव में विशेष रूप से अहोम राजघरानों के मोइदम हैं, वहीं अभिजात वर्ग और प्रमुखों के अन्य मोइदम पूर्वी असम में, जोरहाट और डिब्रूगढ़ के शहरों के बीच के क्षेत्र में बिखरे हुए पाए जा सकते हैं।

Royal burial mounds of Assam now on UNESCO World Heritage List

The Hindu Bureau
NEW DELHI/GUWAHATI

The Charaideo Moidams, a 700-year-old mound-burial system of the Ahom dynasty from Assam, were added to the UNESCO World Heritage List on Friday, making them the 43rd property from India to be included in the prestigious index.

The announcement was made at the 46th session of the World Heritage Committee being held in Delhi.

"This historic recognition brings global attention to the unique 700-year-old mound burial system of the Ahom kings at Charaideo, highlighting the rich cultural heritage of Assam and Bharat," Union Minister for Culture and Tourism Gajendra Singh Shekhawat told the media after the announcement.

An aerial view of the royal burial mounds built by the Ahom dynasty in Charaideo in eastern Assam. AP

Similar to the pyramids of Egypt, the Moidams are earthen burial mounds of the members of the Ahom royalty whose 600-year rule was ended by the British takeover of the region.

The Ahoms adopted the Hindu method of cremation after the 18th century and began entombing the cremated bones and ashes in Moidams at Charaideo.

The highly venerated Moidams make the Charaideo district a tourist destination.

The Moidams are the first from the notheastern States to be recognised as a World Heritage Site in the cultural category. Assam has two other such sites in the natural category - Kaziranga National Park and Manas National Park, both upgraded to tiger reserves.

"THIS IS HUGE. The Moidams make it to the #UNESCO World Heritage list under the category Cultural Property - a great win for Assam. Thank You Hon'ble Prime Minister Shri @narendramodi ji, Members of the @UNESCO World Heritage Committee and to the people of Assam," Chief Minister Himanta Biswa Sarma wrote on X.

He said the Charaideo Moidam embodies the deep spiritual belief, rich civilisational heritage, and architectural prowess of Assam's Tai-Ahom community.

The Moidams were nominated as India's official entry in 2023.

Of the 386 Moidams explored so far, 90 at Charaideo are the best preserved, representative, and most complete examples of this tradition.

चराईदेव मोइदम के बारे में

- चराईदेव मोइदम असम में ताई अहोम समुदाय की देर से मध्ययुगीन (13वीं-19वीं शताब्दी ई.) टीले पर दफनाने की परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है।
- गुवाहाटी से 400 किलोमीटर से अधिक पूर्व में स्थित चराईदेव, 1253 में चाओ लुंग सुकफा द्वारा स्थापित अहोम राजवंश की पहली राजधानी थी।
- अहोम मृतक परिवार के सदस्यों को चराईदेव में रखना पसंद करते थे, जहाँ पहले राजा सुकफा को दफनाया गया था।
- ऐतिहासिक इतिहास बताता है कि पत्नियों, परिचारकों, पालतू जानवरों और बड़ी मात्रा में कीमती सामान को दिवंगत राजाओं के साथ दफनाया जाता था।
- 18वीं शताब्दी के बाद, अहोम शासकों ने दाह संस्कार की हिंदू पद्धति को अपनाया और चराईदेव में एक मैदाम में दाह संस्कार की हड्डियों और राख को दफनाना शुरू कर दिया।
- अब तक खोजे गए 386 मैदाम में से, चराईदेव में 90 शाही दफन सबसे अच्छी तरह से संरक्षित, प्रतिनिधि और अहोम की टीले पर दफनाने की परंपरा के सबसे पूर्ण उदाहरण हैं।

चराईदेव का महत्व

- "चराईदेव" नाम ताई अहोम शब्द "चे-राय-दोई" से आया है, जिसका अर्थ है "पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक चमकता हुआ शहर।"
- यह अहोम साम्राज्य की पहली राजधानी थी, जिसे राजा सुकफा ने 1253 ई. में स्थापित किया था।
- सुकफा को 1856 में यहीं दफनाया गया था, और यह बाद के अहोम राजघरानों के लिए चुना गया विश्राम स्थल बन गया।
- हालाँकि अहोम ने अपने 600 साल के शासन में कई बार राजधानियाँ बदलीं, लेकिन चराईदेव अपने ऐतिहासिक महत्व के कारण एक प्रतीकात्मक और अनुष्ठान केंद्र बना रहा।
- आज, चराईदेव के मोइदाम प्रमुख पर्यटक आकर्षण हैं।

अहोम के बारे में

- अहोम, जिन्हें ताई-अहोम के नाम से भी जाना जाता है, भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश का एक जातीय समूह है।
- यह जातीय समूह ताई लोगों के वंशजों से बना है, जो पहली बार 1228 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में आए थे, और स्वदेशी लोग जो बाद में उनके साथ जुड़ गए।
- वर्तमान अहोम लोग और संस्कृति प्राचीन ताई लोगों और संस्कृति, साथ ही स्वदेशी तिब्बती-बर्मी लोगों और संस्कृतियों का मिश्रण हैं जिन्हें उन्होंने असम में आत्मसात किया।
- ताई समूह के नेता सुकफा और उनके 9000 समर्थकों ने अहोम साम्राज्य (1228-1826 ई.) की स्थापना की, जिसने 1826 तक आधुनिक असम की ब्रह्मपुत्र घाटी के एक हिस्से पर शासन किया।
- इसने 1826 में ब्रिटिश भारत द्वारा कब्जा किए जाने तक 600 वर्षों तक संप्रभुता बनाए रखी (यंडाबू की संधि)।
- लचित बोरफुकन (1622-1672) अहोम राजवंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हैं।

UPSC Prelims PYQ : 2021

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(a) अजंता की गुफाएँ वाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं।
(b) साँची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है।
(c) पांडु-लेना गुफा मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित हैं।
(d) अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है।

उत्तर: a)

Page 14 : Prelims Fact : Paris Olympics

पेरिस ओलंपिक शुरू हो चुका है और 26 जुलाई से 11 अगस्त, 2024 तक चलेगा।

पेरिस ओलंपिक के बारे में

- पेरिस ओलंपिक, जिसे आधिकारिक तौर पर XXXIII ओलंपियाड के खेल के रूप में जाना जाता है, पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया जाएगा।
- यह आयोजन, जिसे आमतौर पर 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के रूप में जाना जाता है, एक अंतरराष्ट्रीय बहु-खेल प्रतियोगिता है जिसमें दुनिया भर के एथलीट भाग लेते हैं।
- खेलों में शामिल हैं: एथलेटिक्स, एक्वेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, कैनोइंग, साइकिलिंग, घुड़सवारी, तलवारबाजी, फुटबॉल, गोल्फ, जिमनास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, मॉडर्न पेंटाथलॉन, रोइंग, रग्बी सेवन्स, नौकायन, शूटिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइम्बिंग, सर्फिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, ट्रायथलॉन, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन और कुश्ती।

Paris unveils the ultimate spectacle with pomp, fervour and splendour

There has never been a celebration this grand during the 128-year history of the modern Olympiad as the Opening Ceremony, along the Seine, features iconic landmarks before culminating at Eiffel Tower; 78 athletes and officials from 12 disciplines take part from the Indian contingent

PARIS 2024

Y.B. Sarangi
PARIS

Vibrant start: Sharath and Sindhu lead India's contingent at the Opening Ceremony. GETTY IMAGES

The magnificent City of Light, dotted with the spectacular Eiffel Tower and scores of majestic buildings featuring admirable architecture, welcomed the 33rd Olympic Games in a unique way, with the much-awaited Opening Ceremony on the Seine involving a stretch of Paris' rich heritage, here on Friday.

The riot of colours and lights turned the Seine and the pastel city into a surreal place, amalgamating history and contemporariness in a spellbinding show conceptualised by Thierry Reboul and directed by Thomas Jolly, to celebrate the return of the Olympics to the city after a century.

Contrast this to the eighth edition of the Games which were held inside the Yves-du-Manoir Stadium in 1924. The Eiffel Tower was as young as only 35 years and the Roland Garros, the home of French Open for close to a century now, was only 33 and was still a year away from hosting its first Major. Paris' Olympic reincarnation exactly after a century tells a story of the world's evolution as well.

The novel parade, over six kilometres on Seine, took off from the Austerlitz bridge beside the Jardin des Plantes in the evening before passing under several bridges and gateways. It provided the athletes a nice view of some of the Games venues, such as Parc Urbain La Concorde, the Esplanade des Invalides, the Grand Palais and the Iena bridge, where the parade ended before the finale took place at the Trocadero.

Greece, the first host of the Games, led the flotilla of 85 boats carrying 6800 athletes with water fountains adding to the beauty of the setting. A Refugee Olympic Team followed, underlining the times we live in as 205 delegates from different countries and hundreds of thousands of people, including several who watched it free, witnessed the amazing show.

With helicopters keeping a watch overhead, 12 cultural tableaux, a cabaret show by Lady Gaga and stunning musical performances by leading French artists, including Aya Nakamura, broke the monotony of the parade.

71 giant screens, beaming the live action from 170 cameras, and strategically placed speakers allowed everyone to enjoy the magical atmosphere of this show reverberating throughout Paris.

Dressed in their tricolour-themed ceremonial attire, the designer kurta bundi sets for men and sarees for women, the Indians stood out.

78 athletes and officials from 12 disciplines took part in athletes' parade, led by double Olympic medallist shuttler P.V. Sindhu and five-time Olympian Sharath Kamal.

The Indian athletes who took part in the grand event included some prominent names such as four-time Olympian archers Deepika Kumari and Tarundeep Rai, Tokyo Games bronze medallist boxer Lovlina Borgohain, shooters Anjum Moudgil, Sift Kaur Samra, Aishwary Pratap Singh Tomar and Anish Bhanwala, paddler Manika Batra and tennis player Rohan Bopanna.

At twilight, the bridges on the Seine lit up and set the stage for the Olympic flame to take its pride of place.

ओलंपिक के बारे में कुछ बातें:

- ओलंपिक खेलों की शुरुआत प्राचीन ग्रीस में 776 ईसा पूर्व ओलंपिया में हुई थी।

- हर 4 साल में आयोजित होने वाले इस खेल में विभिन्न शहर-राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच एथलेटिक प्रतियोगिताएं होती थीं।
- आधुनिक ओलंपिक को फ्रांस के बैरन पियरे डी कुबर्टिन ने पुनर्जीवित किया था।
- पहला आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में ग्रीस के एथेंस में आयोजित किया गया था।
- ओलंपिक रिंग्स 5 बसे हुए महाद्वीपों (अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया) के मिलन का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत 1924 में फ्रांस के शैमॉनिक्स में हुई थी और इसमें स्कीइंग, आइस स्केटिंग और आइस हॉकी जैसे बर्फ और बर्फ पर खेले जाने वाले खेल शामिल हैं।
- ओलंपिक मशाल रिले की शुरुआत 1936 के बर्लिन खेलों में हुई थी।
- भाग लेने वाले देशों की संख्या 1896 के खेलों में 14 से बढ़कर हाल के संस्करणों में 200 से अधिक हो गई है।
- महिलाओं को पहली बार 1900 के पेरिस ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी गई थी।
- विकलांग एथलीटों के लिए पैराओलंपिक खेल पहली बार 1960 में रोम में आयोजित किये गये थे।

भारत की भागीदारी:

भारत पेरिस ओलंपिक 2024 में विभिन्न खेलों में भाग लेने के लिए तैयार है, जिसमें विभिन्न खेलों में कई पदक जीतने की संभावना है।

1. एथलेटिक्स	- नीरज चोपड़ा (भाला फेंक): मौजूदा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, एक बार फिर पोडियम पर पहुंचने का लक्ष्य। - मुख्य कार्यक्रम: ट्रैक और फील्ड स्पर्धाएँ, जिसमें कई एथलीट स्प्रिंट, लंबी कूद और डिस्कस थ्रो में प्रतिस्पर्धा करेंगे।
2. बैडमिंटन	- पीवी सिंधु (एकल): दो बार की ओलंपिक पदक विजेता, अपने तीसरे पदक की तलाश में। - सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी/चिराग शेट्टी (युगल): शीर्ष युगल जोड़ी, पदक की प्रबल दावेदार। - अश्विनी पोनप्पा/सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी: कई अंतरराष्ट्रीय जीत के साथ होनहार मिश्रित युगल जोड़ी।
3. मुक्केबाजी	- मैरी कॉम (फ्लाईवेट): अनुभवी मुक्केबाज और पूर्व ओलंपिक पदक विजेता। - अमित पंघाल (फ्लाईवेट): पुरुष वर्ग में मजबूत दावेदार। - लवलीना बोरगोहेन (वेल्टरवेट): टोक्यो की कांस्य पदक विजेता, उच्च पोडियम फिनिश का लक्ष्य।
4. निशानेबाजी	- मनु भाकर (10 मीटर एयर पिस्टल, 25 मीटर पिस्टल): कई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ युवा और होनहार निशानेबाज। - सौरभ चौधरी (10 मीटर एयर पिस्टल): लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले और पदक की उम्मीद।
5. कुश्ती	- विनेश फोगट (50 किग्रा): अनुभवी पहलवान और पदक की प्रबल संभावना। - अंतिम पंघाल (53 किग्रा): युवा प्रतिभा और उल्लेखनीय क्षमता।

6. भारोत्तोलन	➢ मीराबाई चानू (49 किग्रा): टोक्यो की रजत पदक विजेता, पेरिस में स्वर्ण पदक जीतने का लक्ष्य।
7. हॉकी	➢ पुरुष टीम: टोक्यो में कांस्य पदक जीतने के बाद, टीम का लक्ष्य स्वर्ण पदक जीतना है। ➢ महिला टीम: हाल के वर्षों में बेहतर प्रदर्शन के साथ मजबूत दावेदार।
8. टेबल टेनिस	➢ मनिका बत्रा: अग्रणी भारतीय खिलाड़ी, जिनमें शानदार प्रदर्शन की संभावना है। ➢ शरथ कमल: अनुभवी खिलाड़ी, जिनके पास काफी अंतरराष्ट्रीय अनुभव है।
9. तीरंदाजी	➢ दीपिका कुमारी: कई अंतरराष्ट्रीय पदक जीतने वाली अग्रणी महिला तीरंदाज। ➢ अतनु दास: पुरुषों की तीरंदाजी स्पर्धाओं में मजबूत दावेदार।
10. जिम्नास्टिक	➢ दीपा करमाकर: अपने प्रोडुनोवा वॉल्ट के लिए जानी जाती हैं, उनका लक्ष्य वापसी कर पोडियम पर पहुंचना है।

UPSC Prelims PYQ : 2021

प्रश्न: वर्ष 2000 में स्थापित लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स इस पुरस्कार के पहले विजेता थे।
2. यह पुरस्कार अब तक ज्यादातर 'फॉर्मूला वन' खिलाड़ियों को मिला है।
3. रोजर फेडरर ने दूसरों की तुलना में सबसे अधिक बार यह पुरस्कार प्राप्त किया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: c)

Term In News : Dark Oxygen

वैज्ञानिकों ने हाल ही में गहरे समुद्र में एक विचित्र घटना की खोज की है, जिसे "डार्क ऑक्सीजन" कहा जाता है।

डार्क ऑक्सीजन के बारे में:

- समुद्र की सतह से हज़ारों फ़ीट नीचे पूर्ण अंधेरे में बनने वाली ऑक्सीजन को डार्क ऑक्सीजन कहा जाता है।

- **यह खोज क्यों महत्वपूर्ण है?**
  - अब तक, यह माना जाता था कि ऑक्सीजन केवल प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनती है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है।
  - महासागरीय प्लवक, बहते हुए पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया समुद्र में ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार प्राथमिक तत्व हैं। ये सभी जीव प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम हैं।
  - इतनी गहराई पर ऑक्सीजन का उत्पादन असंभव माना जाता है क्योंकि पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है।
  - हालाँकि, इस मामले में, पौधों द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं किया जा रहा है।
  - ऑक्सीजन पॉलीमेटेलिक नोड्यूल से निकलती है जो कोयले के ढेर के समान होती है।

- मैंगनीज, लोहा, कोबाल्ट, निकल, तांबा और लिथियम जैसी धातुओं से बने ये नोड्यूल प्रकाश की अनुपस्थिति में भी विद्युत रासायनिक गतिविधि के माध्यम से ऑक्सीजन उत्पन्न कर सकते हैं।
- वे H2O अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित कर रहे हैं।

पॉलीमेटेलिक नोड्यूल के बारे में मुख्य तथ्य:

- पॉलीमेटेलिक नोड्यूल, जिन्हें मैंगनीज नोड्यूल के रूप में भी जाना जाता है, गहरे समुद्र तल के समुद्र तल पर पाए जाने वाले छोटे, गोल संचय होते हैं।
- ये नोड्यूल धातुओं और खनिजों के मिश्रण से बने होते हैं, जिनमें मैंगनीज, लोहा, निकल, तांबा, कोबाल्ट और प्लैटिनम, दुर्लभ पृथ्वी तत्व और लिथियम जैसे अन्य मूल्यवान तत्वों के अंश शामिल हैं।
- ये लाखों वर्षों में एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया के माध्यम से बनते हैं।
- वे एक केंद्रीय नाभिक के चारों ओर संकेंद्रित परतों के रूप में विकसित होते हैं, जो एक खोल का टुकड़ा, एक शार्क का दांत या बेसाल्टिक चट्टान का एक टुकड़ा हो सकता है।
- ये परतें मुख्य रूप से मैंगनीज और लोहे के ऑक्साइड से बनी होती हैं, जिनके साथ अन्य धातुएँ भी जमा होती हैं।
- ये धातुएँ इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, मोबाइल फोन, पवन टर्बाइन, सौर पैनल आदि में उपयोग की जाने वाली लिथियम-आयन बैटरी के उत्पादन के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हैं।
- ये मुख्य रूप से उत्तर-मध्य प्रशांत महासागर, दक्षिणपूर्वी प्रशांत महासागर और उत्तरी हिंद महासागर में पाए जाते हैं।
- ऐसा कहा जाता है कि प्रशांत महासागर के क्लेरियन-क्लिपर्टन क्षेत्र में इतने पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हो सकते हैं कि वे आने वाले दशकों तक वैश्विक ऊर्जा की मांग को पूरा कर सकें।

UPSC Prelims PYQ : 2018

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ सौ हज़ार साल में उलट जाता है।
2. जब पृथ्वी का निर्माण 4000 मिलियन साल से भी पहले हुआ था, तब 54% ऑक्सीजन थी और कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी।
3. जब जीवित जीवों की उत्पत्ति हुई, तो उन्होंने पृथ्वी के शुरुआती वायुमंडल को संशोधित किया।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

उत्तर: c)

Page : 06 Editorial Analysis

A new push in the Bay of Bengal

Harsh V. Pant

Professor at King's College London and is Vice President for Studies and Foreign Policy at Observer Research Foundation, New Delhi

Sohini Bose

Associate Fellow, Neighbourhood Studies at ORF

India hosted the 2nd BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) Foreign Ministers' Retreat in New Delhi earlier this month with a focus on providing an "informal platform to discuss ways and means of cooperating and accelerating action in security, connectivity, trade, and investment within the Bay of Bengal." The retreat was held in preparation for the sixth summit meeting, scheduled for September, in which the BIMSTEC leaders will meet in person for the first time in the post-pandemic era. They are also expected to sign the BIMSTEC Agreement on Maritime Transport Cooperation to improve regional connectivity – a foundational aim of this grouping.

Strengthening ties with eastern neighbours

BIMSTEC is the regional organisation devoted to the Bay of Bengal, with a membership of five South Asian and two Southeast Asian countries, cooperating across seven diverse sectors. It allows New Delhi to engage multilaterally with the other countries of the Bay of Bengal region, which are its eastern neighbours and therefore vital for its economic development, security, and foreign policy imperatives. India also remains intent on solidifying relations with its eastern neighbours as China's growing presence in the Bay of Bengal poses a potential threat to regional stability and New Delhi's position as a preferred security partner in these waters.

Strengthening ties with Bangladesh and Myanmar accords India the advantage of providing its landlocked north-eastern region with access to the sea. Improved ties with Myanmar and Thailand will also lend India the opportunity to have a more profound presence in the Indo-Pacific, as it holds the ASEAN (Association of South East Asian Nations), in which these two countries are members, to be of central importance in its vision of the Indo-Pacific. Thailand reinforced this idea at the retreat by identifying itself as a bridge between BIMSTEC and ASEAN. These priorities were reflected in the opening address by the Minister for External Affairs, S. Jaishankar, when he stated that BIMSTEC represents the intersection of India's 'Neighbourhood First' outlook, the 'Act East Policy', and the SAGAR (Security And Growth for All in the Region) vision.

> The intent of BIMSTEC member states to push forth with a bold vision for the region was evident at the 2nd Foreign Ministers' Retreat

Two parts of the retreat

The retreat was divided into two parts. In the first segment, participants assessed the current state of regional cooperation within BIMSTEC, building on a presentation by India on the implementation of key outcomes of the Ist Retreat. Multiple ideas were shared by the member states including the establishment of Centers of Excellence in member states, focusing on Agriculture, Disaster Management, and Maritime Transport. India announced support for cancer research, treatment, and issuance of e-visas for patients of all BIMSTEC states, while Sri Lanka proposed the inclusion of kidney disease. The need for involving the private sector in trade and promoting young entrepreneurs was also highlighted, as was the importance of connectivity, cyber-security, and countering the trafficking of narcotics and illegal arms.

In the second session, the expectations of each country from the forthcoming summit were discussed. Sri Lanka underscored the need to map mineral resources found in abundance in the BIMSTEC countries and create opportunities for the vertical integration of stages of production within specific sectors in the economies of the countries, enabling them to diversify their production structure. Bangladesh highlighted the need for cooperation in the Blue Economy and urged member states to ban fishing during the breeding season to address the problem of depleting catch in the Bay. Bhutan expounded on the need for collaboration in tourism and cultural exchanges, while Nepal highlighted its 'whole of the region' approach to leverage synergies among member states and transform BIMSTEC into a results-oriented regional forum. Thailand underscored the need for cooperation in non-traditional security domains, and Myanmar added the need to combat online scamming to the list. These proposals will be presented to the heads of state before the September summit.

Bilateral merits

While the retreat was a multilateral milestone for India, it had its bilateral merits too. Mr. Jaishankar met several of his counterparts on the sidelines. He shared with Myanmar India's concerns over the flow of displaced persons, narcotics, and arms across the border and urged for the return of unlawfully detained Indians. He also held a meeting with the Bangladesh Foreign Minister, who requested him to ensure the smooth supply of daily essentials and send a technical team for the Teesta project, signifying another step towards easing this long-pending concern. At the end of the retreat, the Foreign Ministers called on Prime Minister Narendra Modi.

This year marks a decade of India's Act East and Neighbourhood First policies, and the thrust on BIMSTEC is a manifestation of New Delhi's efforts to continue nurturing collaborative growth for national and regional well-being. Thus, Mr. Jaishankar encouraged future collaborations through new energies, resources, and a renewed commitment to cooperation.

It remains to be seen how many of these proposals find culmination at the forthcoming Summit but the intent of the member states to push forth with a bold vision for the region was clearly evident at the retreat.

GS Paper 02 : अंतर्राष्ट्रीय संबंध: भारत और उसके पड़ोसी

PYQ : (UPSC CSE (M) GS-2 2022): क्या आपको लगता है कि बिम्सटेक सार्क की तरह एक समानांतर संगठन है? दोनों के बीच क्या समानताएं और असमानताएं हैं? इस नए संगठन के गठन से भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य कैसे पूरे होंगे? (250 w/15m)

UPSC Mains Practice Question : सदस्यों के साझा मूल्य, इतिहास और हित बिम्सटेक को शांति और विकास के लिए एक साझा स्थान प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं; हालाँकि, क्षेत्रीय एकीकरण के लिए एक मंच के रूप में इसकी भूमिका को सतर्क आशावाद के साथ देखा जाना चाहिए। विश्लेषण करें? (250 w/15m)

संदर्भ:

- भारत ने नई दिल्ली में दूसरे बिम्सटेक विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की, जिससे बंगाल की खाड़ी में सुरक्षा, संपर्क, व्यापार और निवेश में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक अनौपचारिक मंच तैयार हुआ।

पूर्वी पड़ोसियों के साथ संबंधों को मजबूत करना

- बिम्सटेक बंगाल की खाड़ी को समर्पित एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें पाँच दक्षिण एशियाई और दो दक्षिण-पूर्व एशियाई देश शामिल हैं, जो सात विविध क्षेत्रों में सहयोग करते हैं।
- क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा: बंगाल की खाड़ी में चीन की बढ़ती उपस्थिति को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए संभावित खतरे के रूप में देखा जा रहा है। बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों के साथ संबंधों को मजबूत करके, भारत का लक्ष्य क्षेत्र में एक पसंदीदा सुरक्षा भागीदार के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करना है।
- आर्थिक विकास: पूर्वी पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध भारत की आवश्यक समुद्री मार्गों तक पहुँच को सुगम बनाते हैं, विशेष रूप से इसके भू-आबद्ध पूर्वोत्तर राज्यों के लिए।
- भारत-प्रशांत रणनीति: म्यांमार और थाईलैंड के साथ बेहतर संबंध भारत की व्यापक भारत-प्रशांत रणनीति का अभिन्न अंग हैं। ये देश आसियान के प्रमुख सदस्य हैं, जिन्हें भारत इस क्षेत्र के लिए अपने दृष्टिकोण का केंद्र मानता है।
- ये प्राथमिकताएँ विदेश मंत्री एस. जयशंकर के उद्घाटन भाषण में परिलक्षित हुईं, जब उन्होंने कहा कि बिम्सटेक भारत के 'पड़ोसी पहले' दृष्टिकोण, 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) दृष्टिकोण के प्रतिच्छेदन का प्रतिनिधित्व करता है।

रिट्रीट के दो भाग

- रिट्रीट को दो भागों में विभाजित किया गया था।
- पहले खंड में, प्रतिभागियों ने बिम्सटेक के भीतर क्षेत्रीय सहयोग की वर्तमान स्थिति का आकलन किया, जो कि प्रथम रिट्रीट के प्रमुख परिणामों के कार्यान्वयन पर भारत द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुति पर आधारित था।
- सदस्य देशों द्वारा कृषि, आपदा प्रबंधन और समुद्री परिवहन पर ध्यान केंद्रित करते हुए सदस्य देशों में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना सहित कई विचार साझा किए गए।
- भारत ने सभी बिम्सटेक देशों के रोगियों के लिए कैंसर अनुसंधान, उपचार और ई-वीजा जारी करने के लिए समर्थन की घोषणा की, जबकि श्रीलंका ने गुर्दे की बीमारी को शामिल करने का प्रस्ताव रखा।
- व्यापार में निजी क्षेत्र को शामिल करने और युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया, साथ ही कनेक्टिविटी, साइबर-सुरक्षा और नशीले पदार्थों और अवैध हथियारों की तस्करी का मुकाबला करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया।
- दूसरे सत्र में आगामी शिखर सम्मेलन से प्रत्येक देश की अपेक्षाओं पर चर्चा की गई।

- श्रीलंका ने बिम्सटेक देशों में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले खनिज संसाधनों का मानचित्रण करने तथा देशों की अर्थव्यवस्थाओं में विशिष्ट क्षेत्रों के भीतर उत्पादन के चरणों के ऊर्ध्वाधर एकीकरण के लिए अवसर पैदा करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे उन्हें अपने उत्पादन ढांचे में विविधता लाने में सक्षम बनाया जा सके।
- बांग्लादेश ने नीली अर्थव्यवस्था में सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला तथा सदस्य देशों से खाड़ी में घटती पकड़ की समस्या का समाधान करने के लिए प्रजनन के मौसम के दौरान मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया।
- भूटान ने पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जबकि नेपाल ने सदस्य देशों के बीच तालमेल का लाभ उठाने तथा बिम्सटेक को परिणामोन्मुखी क्षेत्रीय मंच में बदलने के लिए अपने 'संपूर्ण क्षेत्र' दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला।
- थाईलैंड ने गैर-पारंपरिक सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया तथा म्यांमार ने सूची में ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटने की आवश्यकता को जोड़ा।

द्विपक्षीय गुण

- भारत-म्यांमार चिंताएँ: श्री जयशंकर ने सीमा पार विस्थापित व्यक्तियों, नशीले पदार्थों तथा हथियारों के प्रवाह के संबंध में म्यांमार के साथ मुद्दों को संबोधित किया तथा अवैध रूप से हिरासत में लिए गए भारतीय नागरिकों की वापसी का आग्रह किया।
- भारत-बांग्लादेश सहयोग: बांग्लादेश के विदेश मंत्री के साथ अपनी बैठक में, श्री जयशंकर से दैनिक आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने और तीस्ता परियोजना के लिए एक तकनीकी टीम भेजने का अनुरोध किया गया, जो लंबे समय से लंबित चिंताओं को हल करने की दिशा में प्रयासों को दर्शाता है।

आगे की राह:

- सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना: बिम्सटेक सदस्यों के बीच सुरक्षा सहयोग पर चर्चा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, विशेष रूप से नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी जैसे अंतरराष्ट्रीय अपराधों का मुकाबला करने में।
- कनेक्टिविटी परियोजनाओं का विकास: भारत सरकार को व्यापार और आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लानी चाहिए। इससे न केवल आर्थिक संबंध बढ़ेंगे बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता में भी सुधार होगा।

बिम्सटेक के बारे में

- पूरा नाम: बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल।
- स्थापना: 1997.
- सदस्य देश: बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड।
- उद्देश्य: क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना।
- मुख्यालय: ढाका, बांग्लादेश।

- सहयोग के प्रमुख क्षेत्र: व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन और संचार, पर्यटन, मत्स्य पालन, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद-रोधी, पर्यावरण, संस्कृति और लोगों से लोगों के बीच संपर्क।

- **महत्व:**
  - दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच पुल बनाना।
  - क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाना।
  - आर्थिक एकीकरण और सहयोग को सुगम बनाना।

- **BIMSTEC के सिद्धांत**
  - संप्रभु समानता
  - क्षेत्रीय अखंडता
  - राजनीतिक स्वतंत्रता
  - आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना
  - शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व
  - पारस्परिक लाभ
  - सदस्य देशों को शामिल करते हुए द्विपक्षीय, क्षेत्रीय या बहुपक्षीय सहयोग का विकल्प न बनना।

- **हाल ही में फोकस:**
  - आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करना।
  - संपर्क और व्यापार को बढ़ाना।
  - जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन को संबोधित करना।

- **भारत के लिए बिम्सटेक का रणनीतिक महत्व**
  - भारत को तीन मुख्य नीतियों को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है:
    - पड़ोस पहले - देश की तत्काल परिधि को प्राथमिकता;
    - एक्ट ईस्ट - भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ना;
    - भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक विकास - उन्हें बांग्लादेश और म्यांमार के माध्यम से बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से जोड़कर।
  - यह भारत को बेल्ट एंड रोड पहल के प्रसार के कारण बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने की अनुमति देता है।
  - यह भारत के लिए अपने पड़ोसियों के साथ जुड़ने का एक नया मंच है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों के कारण दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) निष्क्रिय हो रहा है।

- **बिम्सटेक सार्क से किस प्रकार भिन्न है?**

सार्क	बिम्सटेक
1. दक्षिण एशिया पर नज़र रखने वाला एक क्षेत्रीय संगठन 2. शीत युद्ध के दौर में 1985 में स्थापित। 3. सदस्य देश अविश्वास और संदेह से पीड़ित हैं। 4. क्षेत्रीय राजनीति से पीड़ित हैं। 5. असममित शक्ति संतुलन। 6. अंतर-क्षेत्रीय व्यापार केवल 5 प्रतिशत।	1. दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाला अंतरक्षेत्रीय संगठन। 2. शीत युद्ध के बाद 1997 में स्थापित। 3. सदस्य यथोचित मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं। 4. मुख्य उद्देश्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग में सुधार करना है। 5. ब्लॉक में थाईलैंड और भारत की उपस्थिति से शक्ति संतुलन। 6. एक दशक में अंतर-क्षेत्रीय व्यापार में लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

एक्ट ईस्ट नीति

के बारे में:

- नवंबर, 2014 में घोषित 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी', "लुक ईस्ट पॉलिसी" का अपग्रेड है।
- यह विभिन्न स्तरों पर विशाल एशिया-प्रशांत क्षेत्र के साथ आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक कूटनीतिक पहल है।
- इसमें द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर कनेक्टिविटी, व्यापार, संस्कृति, रक्षा और लोगों से लोगों के बीच संपर्क के क्षेत्र में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ गहन और निरंतर जुड़ाव शामिल है।

उद्देश्य:

- सक्रिय और व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ भारत-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों और रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देना और इस तरह उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) के आर्थिक विकास में सुधार करना जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का प्रवेश द्वार है।

सागर

- क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (SAGAR) की शुरुआत 2015 में की गई थी। यह हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के लिए भारत की रणनीतिक दृष्टि है।

- SAGAR के माध्यम से, भारत अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को गहरा करना चाहता है और उनकी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं के निर्माण में सहायता करना चाहता है।
- इसके अलावा, भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना चाहता है और यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हिंद महासागर क्षेत्र समावेशी, सहयोगी बने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करे।
- SAGAR की मुख्य प्रासंगिकता तब उभर कर आती है जब इसे समुद्री क्षेत्र को प्रभावित करने वाली भारत की अन्य नीतियों जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी, प्रोजेक्ट सागरमाला, प्रोजेक्ट मौसम, भारत के रूप में 'नेट सुरक्षा प्रदाता', ब्लू इकोनॉमी पर ध्यान केंद्रित करना आदि के साथ देखा जाता है।

Mapping : Tiger Reserves of India

भारत में टाइगर रिजर्व, धारीदार बड़ी बिल्लियों और उनके आवास का संरक्षण

- भारत में टाइगर रिजर्व धारीदार बड़ी बिल्लियों (बाघों) के लिए विशेष रूप से नामित संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं और उन्हें संरक्षित और सुरक्षित रखते हैं।
- इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत स्थापित किया गया है जिसे बाघों के आवास को संरक्षित करने और उनकी आबादी बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था।
- एक टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य के रूप में भी मौजूद हो सकता है। उदाहरण के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का पार्क आदि जो एक राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य भी है।

बाघ संरक्षण का विस्तार, भारत में 54 टाइगर रिजर्व

- भारत में कुल 54 टाइगर रिजर्व हैं, जो कुल 75,796.83 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की सुरक्षा करते हैं।
- यह देश की कुल भूमि का 2.3% से अधिक है, जो 1973 में 18,278 वर्ग किलोमीटर को कवर करने वाले मूल नौ रिजर्व से उल्लेखनीय वृद्धि है।
- पहला टाइगर रिजर्व 1973 में झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था।
- हाल ही में घोषित बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। ये रिजर्व भारत में रहने वाले बाघों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।

भारत में राज्यवार बाघ अभयारण्य

टाइगर रिजर्व	राज्य	वर्ष
आंध्र प्रदेश	नागार्जुनसागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व	1982-1983
अरुणाचल प्रदेश	पक्के टाइगर रिजर्व	1999-2000
	नमदफा टाइगर रिजर्व	1982- 1983
	कमलांग टाइगर रिजर्व	2016-2017
असम	ओरंग टाइगर रिजर्व	2016
	नामेरी टाइगर रिजर्व	1999-2000
	मानस टाइगर रिजर्व	1973-1974
	काजीरंगा टाइगर रिजर्व	2008-2009
बिहार	वाल्मीकि टाइगर रिजर्व	1989-1990
छत्तीसगढ़	उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व	2008-2009
	इंद्रावती टाइगर रिजर्व	1982-1983
	अचानकमार टाइगर रिजर्व	2008-2009
झारखंड	पलामू टाइगर रिजर्व	1973-1974
कर्नाटक	नागरहोल टाइगर रिजर्व	2008-2009
	दंडेली-अंशी (काली) टाइगर रिजर्व	2008-2009

Will be continue.....